



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 622] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1984/पोष 1, 1906
No. 622] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1984/PAUSA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1984

अधिसूचना

का.प्र. 956(अ) — केन्द्रीय सरकार ने, आनकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/9/84—विधिक गैल तारीख 4-12-84 के अधीन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ के न्यायिक जाल की वास्तव राजस्थान राज्य के अन्तर्गत में अपर विशेष न्यायालय की स्थापना की है,

और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ के न्यायिक जाल में किए गए इसमें उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित अपराधों की वास्तव एक मामला उत्पन्न हो गया है;

और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को इसके उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की वास्तव एक लिखित रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 7 का उपखण्ड (2) के अधीन घोषणा करने के लिए अनुसूची पल्लवित है;

और केन्द्रीय सरकार की चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की उक्त रिपोर्ट पर, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपखंडों, अन्य मामलों के लक्ष्य अंतर्गत नियमितियों तथा अन्य सभी सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, यह राय है कि यह सभीषीत है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के अन्तर्गत में स्थापित अपर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतः, प्रत्येक केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त अपराधों का राजस्थान राज्य के अन्तर्गत में स्थापित अपर विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा।

[प्र. सं. 5/4/84-विधिक गैल]

जेम कुमार, सचिव

अनुसूची			
क्रम सं.	मामले की विनिर्दिष्टता	अपराध	न्यायिक जाल जिसमें अपराध किए गए थे।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मामला सं. आरम्भ 7/84 एसआईयू-III एसआईसी/सीबीआई, नई दिल्ली तारीख 29 फरवरी, 1984	1. याल हुरण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) की धारा 4 और 5	चंडीगढ़
		2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 15) की धारा 120ब, 312, 363, 395 और 506	

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
New Delhi, the 22nd December, 1984

NOTIFICATION

S.O. 956(E):—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984), has established an Additional Special Court at Ajmer in the State of Rajasthan in relation to the judicial zone of Chandigarh in the Union territory of Chandigarh under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 1/9/84-Legal Cell, dated the 4th December, 1984;

And, whereas, a case has arisen involving scheduled offences, specified in the schedule annexed hereto, committed in the judicial zone of Chandigarh in the Union territory of Chandigarh;

And, whereas, the Administration of the Union territory of Chandigarh has forwarded to the Central Government a report in writing containing a request for making a declaration under sub-section (2) of section 7 of the said Act in respect of the offences specified in the schedule annexed hereto;

And, whereas, the Central Government, having regard to the said report of the Administration of the Union territory of Chandigarh, the provisions of sub-section (2) of section 4 of the said Act, the facts and circumstances of the said case and all other relevant factors, is of the opinion that it is ex-

pedient that the said offences should be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby declare that the said offences shall be tried by the Additional Special Court established at Ajmer in the State of Rajasthan.

[F. No. 5/4/84-Legal Cell]
PREM KUMAR, Secy.

THE SCHEDULE

S. No.	Particulars of the case	Offences	Judicial zone in which the offences were committed
1	2	3	4
1.	Case No. RC 7/84-SIU III/SIC/CBI, New Delhi dated 29th August, 1984.	1. Sections 4 and 5 of the Anti-Hijacking Act, 1982 (65 of 1982). 2. Sections 120B, 342, 363, 395 and 506 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).	Chandigarh